जल संकट की आहट और जन–भागीदारी

संजय चौधरी

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ख्नई दिल्ली
ई–मेल : sanjayc1965@gmail.com, sanjayc.crri@nic.in

सारांश

हमारे देश में जल संकट का मुद्दा पिछले कई सालों से उठाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से यह समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है, उसने दुनिया के कई देशों के लिए अघोषित युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अगर अपने देश की बात करें तो, नीति आयोग भी ये बता रहा है कि आज करीब आधा भारत गम्भीर जल संकट की चपेट में है। यह संकट गंभीर इसलिए है क्योंकि कभी हमारे यहां सूखा पड़ता है और कभी सैलाब की स्थिति होती है और इसके बाद जो दिन बचते हैं, उसमें अधिकांशत(कोलन) लोगों को उपयोग के लिए गंदा पानी ही मिल पाता है। आंकड़ों की मानें तो, भारत में 70 प्रतिशत पानी गंदा है और 4 में से 3 भारतीय इसी गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। स्पष्ट है कि स्थिति चिंताजनक है और युद्धस्तर पर समाधान की मांग करते हैं। लेकिन समाधान की बात करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि सरकारी योजनाओं की तुलना में सामूहिक एवं सामुदायिक प्रयासों को किसी भी प्रकार कमतर नहीं आंका जा सकता है। पानी के मामले में जन–भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी की हर एक बूंद अनमोल है तथा हर बूंद को बचाने के प्रयास होने चाहिए। जल संबंधी जो अटल सत्य है, वह यही बताता है कि जल है तो हमारा कल है इसलिए जल के भारतीय जानकारों ने सभ्यता के आरंभ से ही बड़े बांधों एवं विशाल जल परियोजनाओं से अधिक महत्व छोटे–छोटे जोहड़ों, पोखरों, जल–कूपों तथा जल–संचय की घरेलू एवं सामुदायिक विधियों को दिया है। मंदिरों के साथ सरोवरों की व्यवस्था एवं प्रत्येक धार्मिक कर्म–कांड को जल से जोड़ने की परंपरा यही बताती है कि जल का संरक्षण और संवर्धन मानव के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। आज, जल संरक्षण की इन्हीं पारंपरिक विधियों को दुबारा हर गांव, शहर और कस्बों अर्थात घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

की–वर्ड : जल संकट, प्रदूषण, जल संचय, जल संवर्धन, जन भागीदारी, जल–समृद्धि।

Abstract

The core issue of water crisis in our country is being raised for the last several years. But the way in which this problem is becoming increasingly serious at present, has created an undeclared war-like situation for many countries of the world. If we talk about our country, NITI Aayog has already stated that today almost half of India is in the grip of serious water crisis. This crisis is serious because sometimes we have to face droughts and at other times there are floods. For the rest of days, that are left, mostly people get only dirty water for use. According to statistics, 70 percent of the water in India is dirty and 3 out of 4 Indians are forced to drink this dirty water. It is clear that the situation is worrisome. It demands immediate action and an ever-lasting solution. But while talking about solutions, we have to keep in mind that collective and community efforts cannot be undermined in any way as compared to the government schemes and official efforts. Public participation matters because every single drop of water is precious and efforts should be made to save every drop. The irrevocable truth about water is that, 'water is our future'. In India, we have always given importance to small dams, ponds, water wells and individual and community methods of water harvesting since the beginning of civilization. The arrangement of the ponds along with the temples and co-relating every religious ritual with water, suggests that the conservation of water is one of the primary duties of human beings. Today, these traditional methods of water conservation need to be revived and propagated to every village, city and town.

प्रस्तावना

दुनिया में गहराते जा रहे जलसंकट पर जारी एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान समेत 17 देश अत्यधिक जलसंकट वाली श्रेणी में पहुंच चुके हैं। भारत की बात की जाए तो चेन्नई के बाद अब दिल्ली की स्थिति खतरे के निशान को पार करती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए अध्ययन में 445 नदियों में से 275 नदियां प्रदूषित पाई गईं हैं। विश्व भर में साफ पानी की अनुपलब्धता के चलते ही जल जनित रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। हमारे देश के कई हिस्से हर साल पानी की कमी से प्रभावित होते हैं और पानी की

इस समस्या को हम सामान्य बात समझने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पानी की कमी, सूखा और जल जनित बीमारियों के प्रति आज हम बिल्कुल उदासीन हो गए हैं।

जल संकट की भयावहता

पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे देश के लोग सबसे अधिक भूमिगत पानी के ऊपर निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि अमेरिका और चीन जितना पानी मिलकर जमीन से निकालते हैं उतना पानी अकेले भारत में निकाला जाता है। भारत में पीने के पानी का आधे से अधिक भाग भूमिगत भंडार से पूरा होता है तथा देश में जितना पानी जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है, उसका 89 प्रतिशत कृषि कार्य में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। घर के अन्य कार्यों के लिए 9 प्रतिशत इस्तेमाल होता है जबकि 2 प्रतिशत पानी का उपयोग उद्योग–धंधों में होता है।

देश में भूमिगत भंडार को इतनी तेजी से ,ाली किया जा रहा है कि हमारे अधिकांश राज्यों में यह भंडार लगभग ,ाोखला हो चुका है। आज देश जल संकट के मुहाने पर ,ाड़ा है लेकिन अधिकतर देशवासी अपनी जिम्मेदारी से आंखें मूंदकर बैठे हैं। क्या ये बात चौंकाने वाली नहीं है कि हमारे देश में साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% बचाया जाता है? जल संचय का यह प्रतिशत विश्व में सबसे कम है और इससे पता चलता है कि लोग अनमोल संपदा की सुरक्षा के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो भारत 2025 तक भीषण जल संकट वाला देश बन जाएगा।

जल और हमारा इतिहास

हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब भी देश में जल संकट होता था, तब राजा–महाराजा ,ाुद सीधे समस्या के समाधान से जुड़ जाते थे। पिछले कुछ दशकों में हमने यही ,ाजाना ,ाो दिया, जिसका ,ाामियाजा हम भुगत रहे हैं। धीरे धीरे व्यक्तियों और समुदायों ने जल प्रबंधन से हाथ ,ाींच लिए और सरकार को यह जिम्मेदारी सौंप दी, जबकि पहले हमारे देश में किसी भी सरकार द्वारा पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता था। एक और नकारात्मक प्रवृत्ति यह विकसित हुई है कि बारिश के पानी के इस्तेमाल और इकट्ठा करने के आसान व पारंपरिक तरीकों में कमी आई है, जबकि एक ओर बांधों के माध्यम से नदियों तथा दूसरी ओर नलकूपों के माध्यम से भूजल का दोहन बढ़ गया है।

नदियों और जलाशयों का पानी बारिश के पानी का छोटा सा हिस्सा मात्र है, जबकि उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले के समय में जिस तरह तालाबों और टंका के माध्यम से बारिश के जल को जमीन के अंदर पहुंचाया जाता था वह भी अब आबादी बढ़ने और शहरीकरण के कमजोर कानूनों के कारण समाप्त होता जा रहा है। देश में पानी की उपलब्धता और उसका विभाजन भी असमान है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 84 प्रतिशत ग्रामीणों के पास साफ पानी का कनेक्शन नहीं है, वहीं 75 प्रतिशत घरों में पीने के पानी की उपलब्धता घर के अंदर नहीं है। पहले जल की सामुदायिक व्यवस्था थी जबकि अब यह व्यवस्था सरकारी नियंत्रण में आ गई है।

जल को समुदाय से जोड़ने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता में जल ही जीवन है का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वैदिक साहित्य में जल स्रोतों, जल के महत्व, उसकी गुणवत्ता एवं संरक्षण की बात बारबार की गई है। जल की सामूहिक एवं नगरीय व्यवस्था के प्रतीक हैं– 3000ई.पू .में निर्मित बलूचिस्तान एवं कच्छ में पत्थरों से बने प्राचीन बाँध। लगभग इसी काल ,ांड में सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े–बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया जहां वर्षाजल का संग्रह किया जाता था। हमारे पूर्वजों का अटल विश्वास था–हर परिवार में एक टंका, गाँव में मंदिर एवं चारागाह। बड़े टंका या इरिस पूरे गाँव की आवश्यकता को पूरा करते थे और इनके रखरखाव में जन–जन की भागीदारी रहती थी।

सरोवरों अथवा टंकाओं का उपयोग बाढ़ को रोकने, मृदा अपरदन रोकने तथा भूगर्भीय जलस्रोतों को रिचार्ज करने के लिये किया जाता था। इनका प्रबंध किसी ग्राम प्रमुख या धर्मगुरु अथवा पूरे गाँव के जिम्मे होता था। दक्षिण भारत में टंकाओं को मंदिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जोड़ा गया। साथ ही टंकाओं का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिये भी किया गया था। चोल राजाओं ने वर्षाजल संरक्षण के लिये बहुत से टंकाओं का निर्माण कराया था। प्राचीन काल के सभी मंदिरों में टंका अथवा सरोवरों की व्यवस्था के द्वारा न केवल दर्शनार्थियों व आगंतुकों को जल उपलब्ध कराने की परंपरा रही है बल्कि भूजल स्तर को भी बनाए रखने के लिये इन्हें कुछ सौ साल पहले तक उपयोग में लाया जाता रहा है।

मंदिरों के साथ सरोवरों की व्यवस्था ने जल को लोगों की आस्था का विषय बना दिया एवं सरोवरों की सफाई, गाद निकालने व इसके रखरखाव के कार्य से भावनात्मक रुप से जोड़ दिया। प्रत्येक धार्मिक कर्म–कांड को जल से जोड़ने की परंपरा का भी यह सामाजिक प्रभाव पड़ा कि जल के संरक्षण और संवर्धन को मानव के प्राथमिक कर्तव्यों में गिना जाने लगा। सामान्य जन के सामर्थ्य एवं सहभागिता की शक्ति से परिचित जल के भारतीय मनीषियों एवं विद्वानों ने सभ्यता के आरंभ से जल को जमा करने के लिए छोटे–छोटे जोहड़ों, छोटे देसी बांधों, पोखरों, जल–कूपों तथा जल–संचय की घरेलु एवं सामुदायिक विधियों को अधिक महत्व दिया एवं इसमें समाज के हर वर्ग को सम्मिलित किया गया।

जल–व्यवस्था: क्या है आवश्यकता ?

संसाधनों की प्राकृतिक उपलब्धता की दृष्टि से देखें तो हमारे देश में पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोगों में कमी ये है कि पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल के प्रति हम पूरी तरह से उदासीन होते जा रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में हर साल 3 हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है जबकि यहां हर साल 4 हजार बिलियन क्यूबिक मीटर बारिश होती है। इतनी अधिक वर्षा होने के बावजूद जल संकट की समस्या देश में इसलिए है क्योंकि हम बारिश के जल का संग्रह नहीं कर पाते हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि जल का संग्रह, संवर्धन और संरक्षण करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास करने के प्रति लोगों में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं है।

हमारे देश में भौगोलिक विविधता के कारण जल से संबंधित समस्याएं भी विविध एवं जटिल हैं। इसलिए, इन समस्याओं से निपटने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इसके लिए देश के अलग–अलग हिस्सों में, अलग–अलग तरीके से प्रयास करने होंगे। स्वाभाविक है कि स्थानीय नागरिक सरकारों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जल–समृद्धि के प्रयासों में पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों को भी सम्मिलित किया जाए। यदि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार जल संकट का सामना करने के लिए रणनीति तैयार की जाए तो वह अधिक कारगर हो सकती है।

भारत सरकार ने जल संकट का समाधान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। इस मंत्रालय ने लक्ष्य बनाया है कि साल 2024 तक देश के सभी घरों में नल का जल उपलब्ध कराया जाएगा। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 74वें अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक समुदाय के सामने इसी लक्ष्य की घोषणा करते हुए बताया कि प्आने वाले पांच वर्षों में हम, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। संसद में बजट 2019 प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने भी ये घोषणा की थी कि सरकार पानी के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर भी काम करेगी।

लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई सरकार या सरकारी व्यवस्था बिना जन भागीदारी के अपने मंतव्यों और उद्देश्यों में सफल हो सकती है ? हमारे देश में सरकारी प्रयासों की सफलता इसलिए संदिग्ध हो जाती है क्योंकि यहां लोग धरती से अंतिम बूंद तक पानी निकालना जानते हैं, लेकिन उसे वापस भरना नहीं। जमीनी सच्चाई यही है कि सरकार जल आपूर्ति की व्यवस्था तो कर सकती है लेकिन जल संरक्षण का वृहद कार्य केवल सामुदायिक एवं सामूहिक स्तर पर ही संभव है।

जल के जानकार एवं जल–प्रबंधन से संबद्ध विशेषज्ञ यह मानते हैं कि सरकारी नियंत्रण में जल–व्यवस्था होने के कारण आम भारतीय लापरवाह होता चला गया। इसको लक्षित करके वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में लोगों की आदतें बदलने की बात भी कही। एक सौ तीस करोड़ देशवासियों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए देश के प्रधानमंत्री अपने हर सार्वजनिक संबोधन में इसी बात को दोहराते हैं। जल संकट की समस्या के निदान के लिए जरूरी है कि देश में इसके समाधान के प्रयासों में सामान्य जन को जोड़ा जाए। किसी लक्ष्य की पूर्ति में जब जन–जन का सहयोग जुड़ता है तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सबके सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से कई बार असंभव कार्य भी संभव होते देखे गए हैं।

जल–समृद्धि के लिए जन–भागीदारी के दृष्टांत

जल संकट और आसन्न बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रहे मानव को फिर से सरल जीवनशैली और संसाधनों के समझदारी व विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाना ही होगा। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि पारम्परिक जानकारी और तकनीक के बारे में मात्र कहने–सुनने से कुछ नहीं होगा, हम में से हर एक को उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। पूरे समुदाय की संकल्प–शक्ति को उभारने तथा जन–भागीदारी और जन–सहयोग की भावना विकसित करने के लिए गांवों में विद्यालय के बच्चों को भी जागरूकता अभियान के अन्तर्गत शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे भविष्य के निर्माता हैं। आसन्न संकट इतना भयावह है कि पढ़ना–पढ़ाना और रटना–रटाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हम सबको उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

जल के संबंध में जन–जागरण के लिए हमें उन कहानियों, उन उदाहरणों का प्रचार–प्रसार भी करना होगा जो सच्ची व प्रेरणादायक हैं और जो दुनियाभर के लिए बनाए गए टिकाऊ विकास के लक्ष्य की ओर समाज को ले जाती हैं। हमारे देश में कई ऐसी मिसालें हैं जहां जल संकट से निजात पाने में लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजस्थान के लोगों ने मरी हुई एक या दो नहीं, बल्कि सात नदियों को फिर से जीवन देकर ये साबित कर दिया है कि अगर कोई समुदाय ठान ले तो सामूहिक शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है। इसी प्रकार, राजस्थान के कबीरधाम में, ोतों में बनाए गए छोटे तालाबों से एक बड़ा बदलाव आया है।

भारतीय समाज में राजेंद्र सिंह, अनुपम मिश्र जैसे अनेक हस्तियों ने जल–संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है लेकिन जब पूरा समुदाय जल की बचत के ऐसे किसी कार्य में जुटा तो उसका जादुई परिणाम हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जन्मीं अमला रुइया ने राजस्थान के लोगों के सहयोग से वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत ढेरों चेक डैम बनवाए जिसने दो लाख से भी अधिक लोगों की पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर दिया। तेलंगाना के थिमाईपल्ली में पानी के टैंक के निर्माण से गाँवों के लोगों की जिंदगी बदल गई। तमिलनाडु के वेल्लोर में नागनदी को पुनर्जीवित करने के लिए 20 हजार महिलाओं के सामूहिक प्रयास की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की।

बेंगलुरु शहर को कभी झीलों, तालाब और टैंक में वर्षाजल का संचय करने के बाद बसाया गया था। किसी समय इस शहर में 1500 से अधिक झीलें हुआ करती थीं लेकिन एक के बाद एक सभी झीलें अतिक्रमण का शिकार हो गईं और केवल 60 का अस्तित्व ही बच पाया। उसी बेंगलुरु की सरजापुर रोड पर स्थित रिहायशी कॉलोनी प्रेनबो ड्राइव्प के 250 घरों में पानी की सप्लाई तक नहीं थी। आज यह कॉलोनी पानी के मामले में आत्मनिर्भर है और यहां से दूसरी कॉलोनियों में भी पानी सप्लाई होने लगा है। यह संभव हुआ है मिल–जुलकर पानी बचाने, संग्रह करने और गंदे पानी को पुनः इस्तेमाल लायक बनाने से।

भीषण जल संकट के दौर से गुजर रहे कई हिमालयी राज्यों ने जल–धाराएं सूखने के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उदाहरण के लिए सिक्किम के रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (आरएमडीडी) ने 4–5 वर्षों में 700 धाराओं को पुनजीर्वित करके दिखाया है। इस काम में स्थानीय समुदाय और सामाजिक संगठनों की मदद ली गई। 'धारा विकास' नामक कार्यक्रम के तहत धाराओं के कैचमेंट क्षेत्र में छोटे–छोटे गड्ढे बनाकर पानी रोका गया। जन भागीदारी के इन कार्यक्रमों ने कई मृत हो चुके एक्वाफर (जलीय परत) को पुनर्जीवित किया गया है। कुछ ऐसे ही सफल प्रयास नागालैंड, मेघालय जैसे अन्य राज्यों में भी हुए हैं ।

सामुदायिक और सामाजिक पहल की एक और अद्भुत मिसाल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में महिलाओं ने श्रमदान कर पांच चाल–,ाल (तालाब) तैयार किए जिनमें हजारों लीटर वर्षाजल एकत्र हो चुका है। इसी प्रकार, पश्चिम सिंहभूम जिले के सौ स्कूलों में जल सेना का गठन किया गया है जो पानी बचाने का कार्य कर रहे हैं। स्कूलों में सोकपीट, सोख्ता आदि का निर्माण भी किया जा रहा है जिससे सभी लोगों को जल संरक्षण की दिशा में प्रेरित किया जा सके। जल संरक्षण के लिए स्कूलों ने रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम शुरू किया है। देखने में आया कि इस तकनीक से इतना जल एकत्र हो जाता है कि दूसरे स्त्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तथा लोग स्वंय ही आकर इस अभियान से जुड़ने लगे हैं।

जन–भागीदारी एवं जल–समृद्धि के उपाय

देश में पानी की समस्या अपने चरम पर है लेकिन खुलेआम इसकी बर्बादी भी हो रही है। हमें यह समझना और समझाना होगा कि जल और जलवायु की अवहेलना करके हम अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। पानी एक अनमोल प्राकृतिक उपहार है और हमें इसे सहेज कर रखना होगा। पानी की कमी को वही लोग समझ सकते हैं जो इसकी कमी से दो चार होते हैं। समस्या ये है कि हमें भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं है और न ही हम इसके बारे में सोचना चाहते हैं। अगर विकास की अंधाधुंध दौड़ में मनुष्य इसी तरह अंधा होकर चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी अनमोल जल से सदा के लिए वंचित हो सकती है।

दैनिक जीवन में हमें विवेक से काम लेना होगा। जरूरी नहीं है कि हम सभी भगीरथ बन जाएं, लेकिन दैनिक जीवन में एक–एक बूंद बचाने का प्रयास तो हम सभी कर ही सकते हैं। बारिश से पहले गांवों में छोटे–छोटे डैम और बांध बनाकर वर्षा जल को संरक्षित किया जाना चाहिए। शहर में जितने भी तालाब और डैम हैं, उन्हें गहरा किया जाना चाहिए जिससे उनकी जल संग्रह की क्षमता बढ़े। सभी घरों और अपार्टमेंट में वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तभी जलसंकट का मुकाबला किया जा सकेगा। वर्षा जल संग्रहण के लिए कॉलोनी के हर घर में रिचार्ज कुएं बनाए जाने चाहिए।

जल के विशेषज्ञों के अनुसार गांवों, कस्बों एवं शहरों में लोगों को जागरूक करने में समय–समय पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हमेशा उपयोगी होता है। लोगों को बताया जाना चाहिए कि गांव और टोले में कुआं रहेगा तो उसमें बरसात का पानी जायेगा और तभी धरती का पानी और बरसात का पानी मिल पाएगा। ुला हुआ नल बंद करें, अनावश्यक पानी बर्बाद न करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे आदत में शामिल करें। हमारी छोटी सी आदत आने वाली पीढ़ियों को जल के रूप में जीवन दे सकती है। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें ये करना ही होगा।

शहर के संपन्न लोगों को जल संरक्षण के प्रयासों तथा पानी को बचाने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सामान्य तौर पर तीन महामंत्रों–''**जल का कमतर उपयोग, पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण**'' करके शहरों में जल के मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। पढ़े–लिखे लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि समाज में जागरूकता अभियान की शुरुआत करें, उसमें पानी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताएं और पानी बचाने के तरीकों का प्रचार–प्रसार करें। यह भी आवश्यक है कि कुछ जागरूक लोग समाज को जगाएं, समाज को जोड़ें और समाज के साथ जुटें ताकि जल के दुरुपयोग की आदतों में परिवर्तन लाया जा सके।

जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जल शक्ति एप भी बनाए जाने चाहिए जिसे प्लेस्टोर से डाउनलोड करने की सुविधा हो। जल संरक्षण के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय कार्य किये जायें, उनके चित्र इस एप पर अपलोड किये जायें। साथ ही, जरुरी है कि अभिनेता, खिलाड़ी, मीडियाकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, सांस्कृतिक संगठन, कथा–कीर्तन मंडली आदि सभी इस जल आंदोलन का नेतृत्व करें। जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत जुलाई, अगस्त और सितम्बर में वर्षा ऋतु के दौरान पानी को रिचार्ज किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिये जो भी तरीके हम अपनायें, वे किफायती हों और उन्हें आसानी से हर जगह लागू किया जा सके।

जल को प्राकृतिक संसाधन मानने की बजाय आर्थिक संसाधन का दर्जा देने का समय आ गया है। जल समृद्धि की दिशा में प्रयासरत व्यक्तियों और संगठनों का डाटाबेस बनाना और इसके बारे में प्रचार–प्रसार भी महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समूहों की सूची बनाई जाए तथा इनके सराहनीय काम से और लोगों को पानी की बचत के लिए प्रेरित किया जाए। आज के डिजिटल जगत में सोशल मीडिया का सहयोग सबसे असरदार बन रहा है। (हैश) JanShakti4JalShakti हैशटैग पर बातें साझा करके अथवा Hindi.cauverycalling.org जैसे किसी वेब समूह के साथ जुड़कर जल की बचत जैसे सार्थक एवं सर्वहित के कार्यों में सहयोग दिया जा सकता है।

उपसंहार

जल की हर एक बूंद का महत्व है। जल की बर्बादी रोकना, इसका दुरूपयोग बंद करना, जल संसाधन की सुरक्षा व संवर्धन सुनिश्चति करना, वर्षा जल का संचयन–ऐसी छोटी छोटी बातें, सावधानियां एवं जल–संस्कार को अपनाने जैसे उपाय ही हमें जल–बंदी, जल–युद्ध और जल–विहीन भविष्य जैसी भावी विभीषिकाओं से बचा सकती है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि **"अश्विनी के देवदूतों ने इस दुनिया के सृजन के समय जलीय, स्थलीय, वायवीय और दूसरे अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण किया तथा आइए उन सभी जीवों को पृथ्वी पर उपलब्ध पानी से जुड़ी सन्तुष्टि व वरदान प्रदान करें।"** आज, जल संरक्षण की उन्हीं पारंपरिक विधियों को हर गांव, शहर और कस्बों अर्थात घर–घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है क्योंकि यही हमारी परंपरा और हमारा इतिहास रहा है।

Reference

- https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/मन–की–बात
- https://www.downtoearth.org.in
- 'मानव जीवन के लिए जरूरी जल का संरक्षण', संजय चौधरी, ''विज्ञान'' विज्ञान परिषद प्रयाग, अक्टूबर 2005
- 'जीवन प्रदायक जल और हमारी जिम्मेदारी', संजय चौधरी, ''भगीरथ'', केंद्रीय जल आयोग, वर्ष 36, अंक 1, जनवरी 2010
- https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/public-participation-in-tackling-water-crisis-is-extremely-important
- https://hindi-indiawaterportal.org
- https://money.bhaskar.com/news/MON-BUD19-government-may-allocate-rs-10k-crores-for-water-conservation-in-budget-1562055217.html